



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 46]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2015

सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी

कोरम:

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2015 के 2 दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2. वीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी दिनांक 18 जनवरी, 2011, जिसे 31 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित की थी है। यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता कई बार विस्तारित कर चुका है; पिछला विस्तार आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 तक था।

3.1. वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 मार्च 2013 के साथ अपने पत्रों दिनांक 8 फरवरी 2013 द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ चर्चा की गई थी। इस प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 20 सितम्बर 2013 को आयोजित की गई थी। हमारे पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा 19 नवम्बर 2013 को प्रेषित की गई थी।

3.2. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा बताया था कि बीओटी प्रचालक के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए जाने के अद्यतन विकास के मद्देनजर, इसके प्रस्ताव में यातायात, आय अनुमान और घाटा अनुमान में बदलाव किया जा सकता है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, जैसाकि वीपीटी द्वारा बताया गया है, इसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव को प्रभावित करते हुए, वीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा सलाह दी गई थी कि अपने प्रस्ताव को अद्यतन करें और 7 जनवरी 2014 तक प्रस्तुत करें। उसके बाद, वीपीटी के अनुरोध पर, उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 20 फरवरी 2014 तक का समय दिया गया था।

3.3. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2014 द्वारा उद्धरित किया था कि वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्त हो चुका है,

वास्तविकताओं के साथ 2013-14 के अनुमानों को अद्यतन करते हुए अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून 2014 तक समय की मांग की थी। वीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के मद्देनजर, पत्तन को उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून 2014 तक का समय प्रदान किया गया था।

3.4. वीपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 14 अगस्त 2014, 2 सितम्बर 2014 और 3 सितम्बर 2014 द्वारा अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया था। वीपीटी के संशोधित प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ 4 सितम्बर 2014 को विचार-विमर्श किया गया था और उनकी टिप्पणियां 23 सितम्बर 2014 तक भेजने के लिए कहा गया था।

3.5. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2014 द्वारा कैपिटल निकर्षण की लागत वसूल करने के लिए लेवी की शुरूआत किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसके दरमान में शामिल किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त प्रस्ताव उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था।

3.6. वीपीटी द्वारा अगस्त 2014 और सितम्बर 2014 में दाखिल किया गया संशोधित प्रस्ताव और कैपिटल निकर्षण की लेवी के लिए दिसम्बर 2014 के इसके प्रस्ताव में नई संवीक्षा शामिल है और अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए मामला तैयार करने में कुछ और समय लगेगा।

4. इसी बीच, वीपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो चुकी है। उपर्युक्त पैरा 3.4, 3.5 और 3.6 में यथा दिए गए प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च 2015 अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2014 (290)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2015

No. TAMP/13/2009-VPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/13/2009-VPT

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 2nd day of January 2015)

This order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT)

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/13/2009-VPT dated 18 February 2011 which was notified in the Gazette of India on 31st March 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of existing SOR of VPT on couple of occasions; the last extension being till 31 December 2014 vide Order dated 30 September 2014.

3.1. The Proposal filed by the VPT vide its letters dated 8 February 2013 along with its letter dated 22 March 2013 has been taken on consultation with the concerned users/user associations. Joint hearing on the proposal was held on 20 September 2013. The additional information/clarification sought from the VPT vide our letter dated 8 August 2013 has been furnished by the port on 19 November 2013.

3.2. Subsequently, the VPT vide its letter dated 18 December 2013 had stated that in view of latest development of signing of Concession Agreement with BOT operator, the traffic, income estimates and deficit estimates, in its proposal may undergo a change. In view of the above position, brought out by the VPT, having an impact on its general revision proposal, the VPT was advised vide our letter dated 31 December 2013 to update its proposal and submit it by 7 January 2014. Thereafter at the request of VPT, it was allowed time upto 20 February 2014 to file its revised proposal.

3.3. The VPT subsequently, vide its letter dated 2 April 2014 citing that the financial year 2013-14 is over, sought time up to 30 June 2014 to file its revised proposal updating the estimates of 2013-14 with actuals. In view of the submissions made by the VPT, the port was granted time till 30 June 2014 to file its revised proposal.

3.4. The VPT, vide its letters dated 14 August 2014, 2 September 2014 and 3 September 2014, has filed its revised proposal. The revised proposal of the VPT has been taken on consultation with concerned users on 4 September 2014 for their comments by 23 September 2014.

3.5. Subsequently, the VPT vide its letter dated 10 December 2014 has submitted a proposal for introduction of a levy to recover the cost of Capital Dredging and has requested for inclusion in its Scale of Rates. The said proposal has been circulated to the users/user organisations seeking their comments.

3.6. The revised proposal filed by the VPT in August 2014 and September 2014 and its proposal of December 2014 for levy of capital dredging involves fresh scrutiny and it will take some more time for the case to mature for final consideration.

4. In the meantime, the extended validity of the existing SOR of VPT expired on 31 December 2014. Considering the present status of the proposal as brought out in para 3.4, 3.5 and 3.6. above, this Authority extends the validity of the existing SOR of the VPT till 31 March 2015 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, Whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.- III/4/Exty./143/2014 (290)]